इसकी वजह से तीन घंटे में जो तार पहुंचना चाहिए वह मेरा ख्याल है कई दिन में पहुंचता है। इस सन्दर्भ में मैं बता रहा हूं कि जो तार लखनऊ जाना चाहिए वह दूसरे सर्किल के माध्यम से जाता है। यह जो खराबियां हैं उनके सुधार के बारे में मैं जानना चाहता हूं।

मंत्री जी ने अपने जबाब में कहा है कि कम क्षमता का प्रदर्शन करने वाले अन्त: क्षेत्रीय मार्गों पर सीधे एस+4 डी एक्स लिंक मोहैय्या कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं जिससे सर्किट उपलब्धता में सुधार लाया जा सके। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कहां तक आपने कर दिया है, कितना करने जा रहे हैं और कब तक कर देंगे।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बाबू लोग अनुपस्थित रहते हैं और 8 किलोमीटर के जुरिस्डिक्शन में तारों को न भेजकर उनको दूसरे सर्किट में भेज दिया जाता है—इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

SHRI C. M. STEPHEN: Now about this routing of the telegram to channels which are not authorized.... (*Interruptions*) This is one of the areas where delay took place. That was identified. Now instructions have been issued; and they are being strictly conformed to, viz. that only through the specific channels which prescribed must the messages go; and they should not be diverted to different areas, taking too much of time. This is now being enforced, and it is now having results. The Hon. Member asked me about Express S plus 4DX; i.e. in how many stations we have introduced this. In about 50 stations we have already introduced it, and 13 stations are on the agenda immediately. That system is also being introduced—which will bring down the delay to a sizeable extent. The point is that the defects have been identified, and steps are being taken to rectify them; and results have now started being felt. Accumulation of vacancies is one of the reasons, and it is being now handled; and the results are being felt.

1980-81 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन

*83. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1980–81 के दौरान चीनी के उत्पादन में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप इसके मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) क्या चीनी मिलों को इस वर्ष भी गन्ना प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

(ग) यदि देश की चीनी मिलें अपनी पूरी क्षमता से काम करती हैं तो 1981–82 के दौरान कुल कितनी चीनी के उत्पादन का अनुमान है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करेगी कि चीनी मिलें अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग करें और देश भर में चीनी की बढ़ी हुई कीमतें कम हो जायें ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनिर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राय): (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) चीनी वर्ष की गणना अक्टूबर से सितम्बर तक की जाती है। वर्ष 1980–

81 के दौरान चीनी के उत्पादन में गिरावट नहीं आयी है लेकिन यह उत्पादन 1979–80 में गिरकर 38.59 लाख मीटरी टन पर आ गया था जबकि 1978–79 में 58.44 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चालू वर्ष 1980–81 में 7 फरवरी, 1981 तक कुल उत्पादन 29.12 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि पिछले वर्ष की उसी तारीख को यह उत्पादन 22.61 लाख मीटरी टन था। खुले बाजार में चीनी के थोक मूल्य जोकि प्रमुख मंडियों में 1–12–1980 को 795 रुपये से 840 रुपये प्रति क्विंटल पर चल रहे थे, गिरकर 16–2–1981 को 695 रुपये से 740 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं।

(ख) यद्यपि कुछेक राज्यों में चीनी फैक्ट्रियों को इस वर्ष भी अपनी गन्ने की सप्लाई प्राप्त करने में गुड़ और खंडसारी निर्माताओं के साथ भारी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उपलब्धता स्थिति, कुल मिलाकर, बहुत अच्छी है।

(ग) चीनी वर्ष 1981–82 के लिए चीनी के उत्पादन का कोई वास्तविक अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगा। तथापि, 1981–82 में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है इसलिए उस वर्ष चीनी का उत्पादन चालू वर्ष 1980–81 में चीनी के 52 से 54 लाख मीटरी टन के प्रत्याशित उत्पादन की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन होने की आशा की जा सकती है।

(घ) सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं जिनमें कुछेक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :— (1) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करना, (2) 1980–81 में जल्दी पिराई कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहन, (3) नयी स्थापित चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के प्रोत्साहन देने की व्यवस्था को फिर से लागू करना, और (4) खंडसारी के उत्पादन पर लेवी लगाना।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं क्या 1977 से पूर्व सरकार चीनी का निर्यात करती थी? यदि हां, तो किस मात्रा में और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए तो अगर अलग से नोटिस दें तभी बता सकता हूं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूं कि देश में चीनी की कीमत कम हो इसके लिए सरकार निकट भविष्य में क्या कोई कदम उठाने जा रही है ? साथ ही देश में अधिक गन्ना पैदा हो इसके लिए क्या किसानों को कोई इन्सेंटिव देने का सरकार का विचार है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, शुगर की कीमत कम करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि पैदावार बढ़ाई जाए और पैदावार बढ़ाने के लिए हमने बहुत से उपाय किए हैं, जिनमें मिलों को हमने अरलीक्रशिंग के लिए इन्सेन्टिव दिया, जिसकी वजह से 50 फीसदी पिछले साल की निसबत अक्तूबर, नवम्बर में ज्यादा शुगर बनी। दूसरी मिलों को भी इन्सेन्टिव दिया ड्यूटी और दूसरी चीजों में तथा फ्री सेल के लिए ज्यादा कोटा दिया। जो 25 साल पुरानी मिलें हैं, उनकी कैपेसिटी 1250 टन से नीचे है, उनके लिए भी इन्सेंटिव की स्कीम बनाकर दी है, जिसकी वजह से काफी पैदावार बढ़ी है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस साल बावजूद इस बात के कि किसानों को भड़काने के लिए कोशिश की गई. . . . . .

एक माननीय सदस्य : किनके द्वारा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ पोलिटिक पार्टीज की तरफ से । मैं शुगर की बात कर रहा हूं । मीठी-मीठी बात कीजिए और मीठी बात सुनिए ।

उसके बावजूद भी पिछले साल की निसबत इस साल शुगर की पैदावार बहुत बढ़ी है । जनवरी 1977–78 में 11 लाख 55 हजार टन के करीब चीनी की पैदावार हुई थी, उसके मुकाबले में इस साल 12 लाख 19 हजार टन की पैदावार हुई है, यानी काफी बढ़ गई है । यदि मैं आपको 7 फरवरी 1977–78 तक के आंकड़े बताऊं तो शुगर सीजन में 25 लाख 99 हजार टन शुगर बनी थी, जबकि इस साल 7 फरवरी तक 29 लाख 12 हजार टन शुगर पैदा की जा चुकी है । काफी बढ़ोतरी पैदावार में हुई है । मिलों को गन्ना खूब जा रहा है । किसान बहुत खुश है, खूब गन्ना दे रहे हैं । आपकी कोशिशों के बावजूद भी सरकार की नीति बहुत सफल साबित हो रही है ।

श्री सतीश अग्रवाल : कीमतें क्यों नहीं घट रही हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कीमतें भी घट रही हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : कहां घट रही हैं ? दिल्ली की राशन शाप पर चीनी नहीं मिल रही है ।

...व्यवधान...

राव बीरेन्द्र सिंह : कीमत काफी घट गई हैं । इस वक्त भी कीमतें काफी नीचे हैं ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूंकि जनवरी, 1980 में पिछले साल 21 लख टन चीनी आपके पास थी, उसके बाद इस साल में 39 लाख टन चीनी की पैदावार हो गई, जोकि आपके हिसाब से गिर गई और आपके कहने के मुताबिक आपने इम्पोर्ट भी किया था । हमारे देश में मैक्सिमम कन्जम्पशन 54 लाख टन था और देश में चीनी भी काफी थी, तो भी पिछले साल जनवरी के महीने में ओपन-मार्केट में बिहार में 25 रु. किलो और बम्बई में 18 रु० किलो चीनी बिकी और आप कहते हैं कि दाम गिर गए हैं । राशन की दुकानों पर चीनी एवेलेबल नहीं है । बाजार में 7 रु० 8 0पै० के हिसाब से चीनी मिलती है, तो इसके लिए आपके पास क्या जबाब है कि आगे चलकर चीनी के दाम आप कितने घटा सकते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लैवी की शुगर होती है, उसके दाम तो सरकार कन्ट्रोल करती है, वह तो हमने पिछली बार भी 2 रु० 85 पैसे के हिसाब से तकसीम की और जब ओपन मार्केट में दाम ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो आपको यह भी मालूम है कि जितनी फ्री फ्री-सेल कोटे की फैक्ट्रीज की शुगर थी, वह भी फैक्ट्रीज के सहयोग से, मिलों के अपने वालन्ट्री आफर को मन्जूर करके हमने 6 रु० किलो के लगभग तकसीम कराई । वह भी सिर्फ इसलिए कि दाम बहुत बढ़ने लग गए थे और उसके बाद फिर यह सवाल पैदा नहीं हुआ । फ्री सेल की जो शुगर होती है, उसमें फैक्ट्रीज दामों पर बेच सकती है और उसको सरकार कन्ट्रोल सीधे तरीके पर नहीं करती, क्योंकि जो सस्ती शुगर हम जनता को सप्लाई करते हैं, कास्ट प्राइस पर फैक्ट्री से लेकर, फ्री शुगर से उनको अपना नुक्सान पूरा करना होता है ।

SHRI INDRAJIT GUPTA: One way of keeping down or reducing the price of sugar in the open market is not to keep on increasing the price of levy sugar. If the price of levy sugar is increased, you cannot expect the price in the open market to come down. I would like to know from

him, in view of the statement he has made that he expects the production to go up considerably in the present year and next year also, whether they will at least consider reducing the price of levy sugar by that .65 paise which they had increased per kilo in last December, whether the total quota of levy sugar as compared with free sale sugar will be increased to give some relief to the consumer since the production has increased.

RAO BIRENDRA SINGH: The price of 65 per cent of the production which is taken in the levy system is based on certain calculations according to a formula. And this price for levy sugar is paid to the factories with a view to ensure that the producers get a remunerative price for the sugarcane which they supply to the factories. Therefore any drastic reduction in the price of levy sugar that is being paid to the factories will also decrease their capacity to pay the farmer for the sugarcane. Therefore, in view of the need for giving a remunerative price to the farmers and also to supply sugar to the people at a reasonable rate through our public distribution system, all these prices are gone into in detail. At present there is no question of increasing the levy sugar percentage from the present 65 per cent because that has been worked out already, and we think that any increase in the quantity in the levy sugar will only put up the price of sugar in the free market.

SHRI INDRAJIT GUPTA: It must be the opposite.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order please.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: I agree with the Minister that in view of the price paid to the agriculturist a certain incerase in the price of sugar is but natural but the consumer should also not suffer in the open market. Therefore, I would like to know from the Minister whether he would enter into an informal agreement with the mill owners to see that the open market sugar is sold at a reasonably fair price, particularly in the season when there is a great demand for sugar.

RAO BIRENDRA SINGH: We always try to persuade the sugar mills to try and not to make undue profits. And we seek their cooperation as we did last time. They voluntarily offered to hand over all their sugar stocks to the Government for sale at a fixed price.

International Year of Disabled Persons

\+

*86. SHRI R. K. MHALGI:
DR. VASANT KUMAR PANDIT:

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to lay a statement showing:

(a) whether the International Year of Disabled Persons is being organised this year;

(b) if so, the specific schemes which the Central Government propose to undertake, including legislation, to rehabilitate the handicapped persons, specially during the current year; and

(c) the allotments for the various schemes proposed State-wise?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Some of the existing programmes for the disabled persons are being strengthened and new programmes are being evolved in the context of International Year of Disabled Persons. A Working Group has been set up to examine the question of legislation in this field. Significant programes are as under:—

(i) Under the scheme of Integrated Education, Government of India